

उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा नियमावली 2009

1. संक्षिप्त नाम :-

इस नियमावली का नाम "उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा नियमावली, 2009" होगा।

2. प्रारम्भ

यह नियमावली तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी। इस नियमावली के प्रभावी होने पर पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में प्रचलित तत्सम्बन्धी सभी नियमावलियां निष्प्रभावी हो जायेंगी। इसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में उत्तराखण्ड राज्य के विकलांगजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी।

3. परिभाषा

इस नियमावली के अन्तर्गत, जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो :-

- (क) निगम से उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम अभिप्रेत होगा।
- (ख) बस से निगम द्वारा विभिन्न मार्गों पर संचालित की जाने वाली साधारण बसें अभिप्रेत होंगी।
- (ग) राज्य से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है।
- (घ) विकलांगजन की परिभाषा व विकलांगता की श्रेणी विकलांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-2 से अभिप्रेत होगी।

4. विकलांगजनों को उत्तराखण्ड राज्य में निःशुल्क यात्रा सुविधा उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में भिक्षावृत्ति से भिन्न प्रयोजन के लिये यात्रा करने पर दी जायेगी।

5. यात्रा प्रारम्भ करते समय विकलांग व्यक्ति, राज्य के जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा विकलांगता प्रमाण-पत्र (मैडिकल सर्टिफिकेट) अथवा समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा अधिकृत अधिकारी के स्तर से निर्गत परिचय-पत्र अथवा भारत सरकार के स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण-पत्र परिवहन निगम के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

6. उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम, देहरादून द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि कितने विकलांग व्यक्तियों ने एक त्रैमास में निःशुल्क यात्रा सुविधा का उपयोग किया, के मांगपत्र दिये जाने पर अनुमन्य धनराशि निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. यात्रा की सुविधा, विकलांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-2 (न) के अनुसार 40% व उससे ऊपर की विकलांगता से ग्रस्त व धारा-2 (झ) के अनुसार निम्न विकलांगता से ग्रस्त विकलांगजनों को अनुमन्य होगी :-

- (I) अन्धता ;
- (II) कम दृष्टि ;

- (III) कुष्ठ रोग मुक्त ;
- (IV) श्रवण शक्ति का क्रास ;
- (V) चलन निःशक्तता ;
- (VI) मानसिकता मंदता ;
- (VII) मानसिक रुग्णता ;

8. यात्रा के समय निम्न विकलांगजन के साथ उसके सहयोगी/सहयात्री को विकलांगजन की तरह निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी :-
 - (क) जो पूर्ण रूप से अंधे हों ; या अल्पदृष्टि (लो विजन) से ग्रस्त हों ;
 - (ख) जो पूर्ण रूप से मूक व बधिर हों ;
 - (ग) जिनके एक हाथ या पैर अथवा दोनों हाथ या दोनों पैर पूर्ण रूप से कटे हों ;
 - (घ) जिनके एक हाथ या एक पैर या दोनों हाथ या दोनों पैर अपंग (पैरालाइज्ड) हों ;
 - (ङ) जो मानसिक रूप से मंदबुद्धि हो ;
 - (च) जो मानसिक रूप से रुग्ण हों ;
9. परिवहन निगम की बसों से विकलांगजन को पूरे वित्तीय वर्ष में यात्रा की सुविधा अनुमन्य होगी।
10. नगर सेवा बस में भी यह सुविधा अनुमन्य होगी, यदि उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम नगर बस सेवा संचालित करते हों।
11. उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम को विकलांगजनों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये सम्बन्धित विभाग के आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि के अनुसार पारस्परिक सहमति से धनराशि का भुगतान निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा।
12. बस का परिचालक विकलांगजन के द्वारा बिन्दु संख्या 5 में उल्लिखित विकलांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर यात्रा का विवरण अंकित करेगा। विकलांगजन का नाम व विकलांगजन द्वारा प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण-पत्र संख्या/किस सक्षम अधिकारी ने जारी किया; यात्रा कहां से कहां तक की गयी; निगम किराया छोड़कर कितनी धनराशि कर के रूप में वसूल की गयी; मार्ग पत्र में अंकित करेगा। इसी प्रकार प्रतिदिन विकलांगजनों द्वारा की गयी यात्रा के विवरण डिपो स्तर पर रखे जायेंगे; जिसमें निगम किराया का उल्लेख किया जायेगा।
13. उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम प्रत्येक माह लेखा विवरण तथा यात्रा करने वाले विकलांगजनों की संख्या सम्बन्धी विवरण निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे।
14. नियमावली के नियम-5 के क्रम में विकलांगजन अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में गठित मैडिकल बोर्ड से विकलांगता प्रमाण-पत्र (मैडिकल सर्टिफिकेट) प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
15. विकलांगजनों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा निगम की समस्त साधारण बसों में अनुमन्य होगी, यह छूट बस के प्रस्थान करने के स्टेशन से बस के गन्तव्य/अन्तिम पड़ाव तक दी जायेगी। निगम की

बसों जहां तक संचालित हो रही हैं वहां तक उत्तराखण्ड राज्य के विकलांगजनों को साधारण बसों के किराये में छूट प्रदान की जायेगी।

16. यात्री किराये के कुल धनराशि का लगभग 20% विकलांगजन (पैसेंजर टैक्स, यात्री बीमा व यात्री सुविधा धनराशि) एवं उनके सहयोगी सहयात्री से प्राप्त किया जायेगा तथा शेष निगम किराया की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा। उक्त 20% धनराशि में यात्री बीमा का अंश भी सम्मिलित होगा।

(मनीषा पंवार)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
समाज कल्याण अनुभाग-02,
संख्या : 287/XVII-02/2009-06(18)/2004
देहरादून : दिनांक 25 फरवरी, 2009

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. मुख्य आयुक्त, विकलांगजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, 31, सैक्टर-39, नोएडा, उत्तर प्रदेश।
7. आयुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मंडल, नैनीताल/पौड़ी।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
10. आयुक्त विकलांगजन उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
12. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस नियमावली की 200 प्रतियां मुद्रित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सहेला अग्रवाल) 25/2/19
अपर सचिव।